Contribution of industry in GSDP

2848. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the contribution of industry in the Gross State Domestic Product (GSDP) in respect of Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka;

(b) how these compare with the Northern States mainly U.P., Bihar, Rajasthan and Orissa; and

(c) the steps taken by Government to improve industrial performance in the Northern States?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) Estimates of Gross State Domestic Product from Industry (manufacturing) and its Relative share in total GSDP at current prices are as follows:

(Rs. Lakhs)

Sl. No.	Name of State	Current prices		
		1992-93	1993-94(P)	1994-95(Q)
1.	Maharashtra	2099120	2499765	3184364
		(23.70)	(23.86)	(25.85)
2.	Gujarat	1007887	1154557	1343907
		(25.54)	(26.31)	(25.05)
3.	Tamil Nadu	1032240	1064367	1214809
		(23.63)	(21.15)	(20.85)
4.	Karnataka	534863	580878	672986
		(16.20)	(15.32)	(15.47)
5.	Uttar Pradesh	1016910	1086572	1239911
		(14.37)	(13.70)	(13.80)
6.	Bihar	485101	529278	634409
		(15.15)	(14.52)	(14.98)
7.	Rajasthan	291456	334420	N.A
		(11.02)	(11.94)	N.A
8.	Orissa	204234	203608	237815
		(13.49)	(11.74)	(12.10)

Figures within Parenthesis show the percentage share to total GSDP.

P: Provisional

Q: Quick

N.A: Not available

© Industrial development is primarily the responsibility of the State Governments and the Central Government only supports and supplements their efforts.

कोयला खानों और उनके कार्यालयों में नियुक्तियां

2849. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान एस०ई०सी०एल०, रायगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत खानों और कार्यालयों में कितने व्यक्तियों को प्रत्यक्ष नियुक्तियां दी गयी हैं और उन पदों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इन कर्मचारियों को जिन अधिकारियों ने नियुक्त किया है उनके नाम क्या-क्या हैं और उन कर्मचारियों के नाम क्या-क्या हैं, जिन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ग) सम्बद्ध रोजगार कार्यालयों से लिये गये उम्मीदवारों का रोजगार कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है और उनके नियुक्ति आदेश विहित प्रक्रिया के अनुसार जारी

किये गये हैं तथा उन उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विहित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए नियुक्त किया गया है; और

(घ) विदित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए जिन अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सा०ई०को०लि०) के रायगढ़ क्षेत्र में 1994-95 और 1995-96 के दौरान 350 व्यक्तियों को रोजगार दिए गए, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

पदों के नाम	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या		जोड़
	1994-95	1995-96	
माइनिंग सरदार	7	शून्य	7
आई०टी०आई० प्रशिक्षु	शून्य	95	95
आई०टी०आई० तकनीशियन (श्रेणी-1)	शून्य	144	144
सहायक फोरमेन (प्रशिक्षणार्थी)	6	शून्य	6
रोजनदार लोडर	90	शून्य	98
जोड़	111	239	350

(ख) प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, मुख्य महाप्रबंधक रायगढ़ क्षेत्र, सा० ई०को०लि० के प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित पदों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी हैं। ऐसे कर्मचारियों के नामों का ब्यौरा जिन्हें नियुक्ति-पत्र निर्गत किए गए हैं, अनुपत्र में दिया गया है। **(देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 68)**

(ग) कोयला कंपनी, रायगढ़ के अनुसार, रोजगार कार्यालय ने 1970 उम्मीदवारों को प्रायोजित किया था, जिनमें से 350 उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए चयनित कर लिया गया था। कम्पनी के नियमों और क्रियाविधि को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति-पत्र जारी किए गए थे और विहित प्रक्रिया के विरुद्ध किसी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया गया है। रोजगार कार्यालय द्वारा यथा प्रायोजित उम्मीदवारों के नामों से संबंधित जानकारी काफी बड़ी मात्रा में अन्तर्ग्रस्त है। इसके संग्रहण में किए गए प्रयास और नियोजित श्रम लक्षित उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को संदर्भगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

Representations received by joint DGFT Cochin on arrears of CCS

2850. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Joint DGFT, Cochin has received number of representations on account of arrears of CCS payment;

(b) whether Government in certain cases had requested for dropping some issues of objections;

(c) whether even thereafter CCS Accounts of such exporters have not been cleared;

(d) the details of representations received from both Public Sector and Private Sector companies till 31st July, 1996 during the year;

(e) the steps being taken to settle the issues without further delay; and

(f) if so, the details thereof?